



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 284]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 1985/आषाढ़ 12, 1907

No. 284]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 1985/ASADHA 12, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह वचन संकलन को कप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1985

सं. 218/85-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 545(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-
शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा
25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में
ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 77-सीमा-शुल्क/
80, तारीख, 17 अप्रैल 1980 में निम्नलिखित और संशोधन
करती है अर्थात् :—

(क) उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में परन्तु के
स्थान पर निम्नलिखित परन्तु रखा जाएगा अर्थात् :—

“परन्तु यदि उक्त माल के उत्पादन या पैकिंग
करने के अनुक्रम में निकलने वाले स्क्रैप या अपशिष्ट सामग्री

का प्रतिशत कांडला मुक्त व्यापार जोन बोर्ड द्वारा, जो कि
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प सं. 5/19/
74-मु. व्या. जो., तारीख 5 दिसम्बर, 1974 द्वारा नियुक्त
किया गया है, इस बाबत नियत किए गए प्रतिशत से अधिक
है, तो ऐसी आधिक्य मात्रा पर उस मूल सामग्री पर उद-
ग्रहणीय शुल्क के बराबर शुल्क प्रभावित किया जाएगा
जिसमें से उक्त स्क्रैप या अपशिष्ट सामग्री निकला है।”;

(ख) सारणों का लोप किया जाएगा।

[सं० 218-सी. शु/85-का. सं. 305/62/85-एफटीटी]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 3rd July, 1985

NO. 218/CUSTOMS/85

G.S.R. 545 (E).—In exercise of the powers con-
ferred by sub-section (1) of section 25 of the Cus-
toms Act, 1962 (52 of 1962), the Central Govern-
ment, being satisfied that it is necessary in the public

interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 77-Customs/80, dated the 17th April, 1980, namely :—

(a) In the said notification, in paragraph 2, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that if the percentage of scrap or waste material arising in the course of production or packaging of the said goods exceeds the percentage fixed in this regard by the Kandla Free Trade Zone Board appointed by the Resolution of the Government of India in the Ministry of Commerce No. 5/19/74-FTZ, dated the 5th December, 1974, the duty equal to that leviable on the mother material, out of which the said scrap or waste material has arisen, shall be charged on the excess quantity.”;

(b) The Table shall be omitted.

[No. 218 Customs/85-F.No.305/62/85-FTT.]

सं. 219/85-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 546 (अ) :—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13—सीमा-शुल्क/81, ताराख, 9 फरवरी, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में शर्त, (6) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु, उक्त वस्तुओं के विनिर्माण के अनुक्रम में निकलने वाला स्क्रैप या अपशिष्ट सामग्री ऐसे शत-प्रतिशत निर्यात-मुख्य उपक्रमों से उस शुल्क के समतुल्य रकम का संदाय करके निर्यात किया जा सकता है जो उक्त स्क्रैप या अपशिष्ट सामग्री पर उद्ग्रहणीय होता यदि वह ऐसे स्क्रैप या अपशिष्ट सामग्री के रूप में आयोजित किया गया होता :

परन्तु यह तब जब उक्त स्क्रैप या अपशिष्ट सामग्री का प्रतिशत उक्त बोर्ड द्वारा इस निमित्त नियत किए गए प्रतिशत से अधिक नहीं हो :

परन्तु यह और कि यदि उक्त स्क्रैप या अपशिष्ट सामग्री का प्रतिशत उक्त बोर्ड द्वारा इस निमित्त नियत किए गए प्रतिशत से अधिक है तो ऐसी आधिक्य मात्रा पर उस मूल सामग्री पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर रकम प्रभारित की जाएगी जिसमें से उक्त स्क्रैप या अपशिष्ट सामग्री निकले हैं ।”

[सं. 219-सी०शु/85-फा. सं. 305/62/85/ एफटीटी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

NO. 219 CUSTOMS/85

G.S.R. 546 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 13-Customs/81, dated the 9th February, 1981, namely :—

In the said notification, after condition (6), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the scrap or waste material arising in the course of manufacture of the said articles may be cleared from such hundred per cent export-oriented undertakings on payment of an amount equal to the duty which would have been leviable on the said scrap or waste material had it been imported as such scrap or waste material : Provided that the percentage of the said scrap or waste material does not exceed the percentage fixed in this regard by the said Board :

Provided further that if the percentage of the said scrap or waste material exceeds the percentage fixed in this regard by the said Board, an amount equal to the duty leviable on the mother material, out of which the scrap or waste material has arisen, shall be charged on the excess quantity”.

[No. 219 Customs/85-F. No. 305/62/85-FTT.]

SUNIL KUMAR, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 285]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 1985/आषाढ़ 12, 1907

No. 285]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 1985/ASADHA 12, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1985

सं. 216/85/-सीमा-शुल्क

सां. का. नि. 547(अ):— केन्द्रीय सरकार. सीमा-
शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा
25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में
ऐसा करना आवश्यक है, 10 टन से अधिक क्षमता
वाले फोर्कलिफ्ट ट्रकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों
को, तब जब भारत में उनका आयात किया जाए, सीमा-
शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की
पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-
शुल्क के उतने भाग से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते

हुए छूट देती है, जो मूल्यानुसार 40 प्रतिशत की दर
पर संगणित रकम से अधिक है, अर्थात् :—

(i) इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट केवल ऐसे
फोर्कलिफ्ट ट्रकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित
संघटकों को लागू होगी जो तकनीकी विकास
महानिदेशालय के औद्योगिक सलाहकार या
अपर औद्योगिक सलाहकार तथा भारी उद्योग
विभाग के औद्योगिक सलाहकार दोनों के द्वारा
प्रमाणित सूची के अंतर्गत सम्मिलित हैं;

(ii) आयातकर्ता सीमा-शुल्क सहायक बलक्टर के
समक्ष उक्त संघटकों की निकासी के समय यह
साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि उसके पास भारी उद्योग
विभाग और तकनीकी विकास महानिदेशालय
द्वारा ऐसे फोर्कलिफ्ट ट्रकों के निर्माण के लिए
सम्यक् रूप से अनुमोदित कार्यक्रम हैं; और